







संपादकीय

## खतरे का खनन



इसमें दो राय नहीं कि कुदरत द्वारा प्रदत्त उपहारों में पानी के बाद रेत ही प्राकृतिक संसाधन है जो मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। दरअसल, यह हमारे आसपास तेज होते निर्माण कार्यों की जरूरत के चलते भी हुआ है। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की देशव्यापी नुट के चलते नदियों से रेत खनन इन अवैज्ञानिक तरीके से होता है कि यह कालांतर जन-धन की क्षति का कारण सावित होने लगता है। दरअसल, नदी तल से निकाले जाने वाले रेत का हमारे परिस्थितिकी तंत्र पर खास प्रतीकूल असर पड़ता है। हमारे पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव दूरावाही होता है। समय-समय पर हुए अध्ययन इस बात पर बहुत देते हैं कि नदियों के तटों से निकाली जाने वाली रेत का नियमन होना चाहिए वयक्ति जिनका नियमन न होने के परिणाम विनाकारी हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संरक्षण यानी आईआईटी की रोपड़ शाखा ने एक नये अध्ययन में की है। यह अध्ययन बताता है कि व्यास नदी के तटों पर यदि वैज्ञानिक तौर-तरीकों से रेत का खनन किया जाए तो मानसून के दौरान पंजाब में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। दरअसल, अंगांधी खनन से नदी की पानी की धारा अवरुद्ध होती है और मानसूनी वारिश का पानी नदियों में उफान मारकर बरिस्तों की ओर बहने लगता है। खनन से नदियों के टटवंश भी प्रभावित होते हैं। यदि शासन-प्रशासन कायदे से खनन की अनुमति देते हों तो मानवीय फसलों की क्षति को टाला जा सकता है। दरअसल, मानसून में अथाव जलरक्षण की अपाना रास्ता मिलने से वह अपने प्राकृतिक प्रवाह के अनुरूप रहती है। नदी की भंडारण क्षमता अधिक होती है और नियन्त्रित खनन से टटवंश शहरों व गांवों का नुकसान कम करना संभव है। दरअसल, लगातार अवैध खनन से नदियों के निकालों पर खाड़ीय बन जाती है। जो नदी के रसायनिक प्रवाह को बहित करती है। जलरुदी है कि रेत खनन को ताकिंक बनाए जाने के लिये इसका गुणात्मक व मात्रात्मक ढंग जुटाया जाए।

दरअसल, पंजाब सरकार द्वारा मानसून के बाद नदियों और उसके किनारे तलाजट जमा होने में पानी जाने वाली भिन्नता के आकलन के लिये आईआईटी रोपड़ की सेवाएं ली गई थी। आईआईटी की टीम ने रेत खनन में प्रारंभिता लाने के लिये एक प्रभावी नियामक तंत्र बनाने का सुझाव दिया था। इसमें ढंग का उपयोग करके नदी तल का मानविक्रांत भी शामिल था। यह कदम नदी तलों पर खनन की वास्तविक स्थिति को बताने में सक्षम है। अध्ययन में यह बात भी सामने आई कि इस संकट को दूर करने के लिये रेत माफिया पर भी अंकुश लाने का प्रयास किया जाए। साथ ही रेत की नीतामी और खनन की स्थिति के डिजिटलीकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि नदी के किनारों के आसपास रेत खरीदी गई है या नहीं। इसके साथ निर्माण की गुणवत्ता के लिये रेत के ग्रेड निर्धारण का भी सुझाव दिया गया है। निसर्देह, इस दिशा में व्यापक अनुसंधान वर्क की जरूरत है। जो पर्यावरण संरक्षण, त्रुट्यादी निर्माण ढांचे को सुरक्षा प्रदान करने और अन्य सामग्री के नियमन के लिए भी जरूरी है। आईआईटी रोपड़ की इस भूमिका का स्वायत्त किया जाना चाहिए। एक ओर इस प्रयास से जहां अवैध खनन की रोकथाम में मदद मिलेगी, वही हर साल मानसून के दौरान फसलों व जन-धन की स्थिति को कम किया जा सकेगा। निसर्देह, पंजाब में रेत और खनियों के खनन की अपार समावाहा है। जो राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति देने में सहायक सावित हो सकती है। जलरुद इस बात की है कि खनन की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाए। इसकी नीतामी में पारदर्शिता और बैहतर प्रबंधन से बेहतर परिणाम आधिक व पर्यावरणीय दृष्टि से हासिल किये जा सकते हैं। साथ ही दिग्दर्शनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये नदी की चौड़ाई व पुनः रेत पूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खनन स्थलों की निगरानी की जानी चाहिए। यह हमारे पर्यावरण संतुलन की अपरिहार्य शर्त भी है। शासन-प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है।

## सुरंगों के संजाल से जख्मी हिमालय



पौराणिक नगरी जोशीमठ के धंसने के कारण तपोवन-विष्णुवाड जल विद्युत परियोजना की सुरंग के चर्चा में आने के बाद चाराधाम औल वेदर सड़क परियोजना की उत्तरकाशी स्थिति सिलवायर परियोजना की सुरंग सुर्खियों में है।

परियोजना से लेकर पूर्वोत्तर तक पन बिजली के लिए योजनाकारों ने हिमालयी क्षेत्रों को चिन्हित कर रखा है।

हिमालय पर सुरंगों का निर्माण शुरू से चर्चा का विषय रहा है। हिमालय के गर्भ को छलनी करने का समर्थन तो पर्यावरणविद् कर, नहीं सकते मगर भूविज्ञानी भी इसमें संयम की सलाह अवश्य देते हैं।

बाडिया ईंटरस्ट्रूट आफ हिमालय जियोलॉजी के

टनल सहित कुल 218 किमी लम्बी सुरंगें विभिन्न चरणों में हैं दरअसल किसी भी परियोजना में केवल मुख्य सुरंग का काम होता है। जबकि उस मुख्य सुरंगों को खोदने और उसका मलबा बाहर निकलने के लिए भी सुरंगों बनानी होती है, जिनमें एडिट भी कहा जाता है। इसी प्रकार चाराधाम आल वेदर रोड के लिए भी कुछ सुरंगों बन रही हैं, जिनके निर्माण के लिए भी अन्य सुरंगें बन रही हैं। इसलिये सबल उठना लजिमी है कि अगर हिमालय के क्षेत्रों पर हाफ़ अन्दर से इस तरह छलनी करने के लिये जायेंगे तो उसका पर्यावरणीय और अन्य व्यावहारिक असर क्या होगा।

ऋग्वेदिक विशिष्ट भूगर्भीय, भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषांकों के कारण टिरी, पोटी और रुद्रप्रयाम जिलों की कुछ बसियों में इकल भूमिगत निर्माण में इस तरह के हादरे नहीं बात नहीं है। अब तो सुरंगों के धंसने और निर्माणांशी सुरंगों के ऊपर बर्बी बासियों के धंसने की शिकायतें आम हो गयी हैं। सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंडी निर्माणवाली के अनुसार उत्तराखण्ड के साथ-साथ हिमालय पर विजली परियोजनाओं के लिए भी बढ़िया व्यापक वातावरणीय और अन्य व्यावहारिक असर क्या होगा।

क्षेत्र की विशिष्ट भूगर्भीय, भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषांकों के कारण हिमालय में सुरंग निर्माण से भी कुनैतिया खड़ी हो जाती है। दरअसल, हिमालय जिले भूगर्भीय सरक्षणों वाला एक भूकीर्ण दृष्टि से व्यापक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चाढ़ने, धर्म रोड़े रेखाएँ और अस्प्रिंग घासियां वाले चाढ़ने को विदर्नाथ और जहाजरानी मंडी निर्माणवाली के अनुसार उत्तराखण्ड के साथ-साथ हिमालय पर विजली परियोजनाओं के लिए भी बढ़िया व्यापक वातावरणीय और अन्य व्यावहारिक असर क्या होगा।

क्षेत्र की विशिष्ट भूगर्भीय, भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषांकों के कारण हिमालय में सुरंग निर्माण से भी कुनैतिया खड़ी हो जाती है। दरअसल, हिमालय जिले भूगर्भीय सरक्षणों वाला एक भूकीर्ण दृष्टि से व्यापक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चाढ़ने, धर्म रोड़े रेखाएँ और अस्प्रिंग घासियां वाले चाढ़ने को विदर्नाथ और जहाजरानी मंडी निर्माणवाली के अनुसार उत्तराखण्ड के साथ-साथ हिमालय पर विजली परियोजनाओं के लिए भी बढ़िया व्यापक वातावरणीय और अन्य व्यावहारिक असर क्या होगा।

क्षेत्र की विशिष्ट भूगर्भीय, भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषांकों के कारण हिमालय में सुरंग निर्माण से भी कुनैतिया खड़ी हो जाती है। दरअसल, हिमालय जिले भूगर्भीय सरक्षणों वाला एक भूकीर्ण दृष्टि से व्यापक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चाढ़ने, धर्म रोड़े रेखाएँ और अस्प्रिंग घासियां वाले चाढ़ने को विदर्नाथ और जहाजरानी मंडी निर्माणवाली के अनुसार उत्तराखण्ड के साथ-साथ हिमालय पर विजली परियोजनाओं के लिए भी बढ़िया व्यापक वातावरणीय और अन्य व्यावहारिक असर क्या होगा।

क्षेत्र की विशिष्ट भूगर्भीय, भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषांकों के कारण हिमालय में सुरंग निर्माण से भी कुनैतिया खड़ी हो जाती है। दरअसल, हिमालय जिले भूगर्भीय सरक्षणों वाला एक भूकीर्ण दृष्टि से व्यापक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चाढ़ने, धर्म रोड़े रेखाएँ और अस्प्रिंग घासियां वाले चाढ़ने को विदर्नाथ और जहाजरानी मंडी निर्माणवाली के अनुसार उत्तराखण्ड के साथ-साथ हिमालय पर विजली परियोजनाओं के लिए भी बढ़िया व्यापक वातावरणीय और अन्य व्यावहारिक असर क्या होगा।

क्षेत्र की विशिष्ट भूगर्भीय, भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषांकों के कारण हिमालय में सुरंग निर्माण से भी कुनैतिया खड़ी हो जाती है। दरअसल, हिमालय जिले भूगर्भीय सरक्षणों वाला एक भूकीर्ण दृष्टि से व्यापक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चाढ़ने, धर्म रोड़े रेखाएँ और अस्प्रिंग घासियां वाले चाढ़ने को विदर्नाथ और जहाजरानी मंडी निर्माणवाली के अनुसार उत्तराखण्ड के साथ-साथ हिमालय पर विजली परियोजनाओं के लिए भी बढ़िया व्यापक वातावरणीय और अन्य व्यावहारिक असर क्या होगा।

क्षेत्र की विशिष्ट भूगर्भीय, भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषांकों के कारण हिमालय में सुरंग निर्माण से भी कुनैतिया खड़ी हो जाती है। दरअसल, हिमालय जिले भूगर्भीय सरक्षणों वाला एक भूकीर्ण दृष्टि से व्यापक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार की चाढ़ने, धर्म रोड़े रेखाएँ और अस्प्रिंग घासियां वाले चाढ़ने को विदर्नाथ और जहाजरानी मंडी निर्माणवाली के अनुसार उत्तराखण्ड के साथ-साथ





# आजीविका भवन चढ़े भ्रष्टाचार की भेट, शासन के आदेश की उड़ाई धज्जियां

पूरे प्रदेश में करीब 80 करोड़ रुपए और जिले में करीब तीन करोड़ रुपए का मामला



माही की गूँज, अलीराजपुर।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के समूहों की बड़ी संस्था जिसको संकुल स्तरीय संगठन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आजीविका विकास के लिए गतिविधियां सञ्चालित की जाना थी। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों के 159 विकास खंडों में आजीविका भवन बनाने के लिए पंचायत ग्रामीण के बानकर मौखिक आदेश देकर जिला पंचायत के खाते में यह रकम वापस जमा करवा दी गई। इस तरह जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने मिलकर अर्डैस के माध्यम से ठेकेदारों को आजीविका भवन बनाने का ठेका दे दिया और अपर मुख्य सचिव पंचायत ग्रामीण विकास विभाग राष्ट्रीय मुद्रा जुलानिया के आदेश को ताक में रखते हुए उसकी धज्जियां उड़ा दी।

आयोग, मुद्रांक शुल्क/अन्य राशियां मद से आदेश के रूप में जारी की गई थी।

जिले के 6 विकासखंडों में गठित संकुल संगठनों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए सहित कुल एक करोड़ 20 लाख रुपए भी जारी कर दिए गए थे। विश्व सूत्रों से पता चला है कि, राशि जारी होने के कुछ ही महीनों के बाद विना किसी पत्र के कर्मचारियों पर दबाव भवन बनाने के लिए पंचायत ग्रामीण के बानकर मौखिक आदेश देकर जिला पंचायत के खाते में यह रकम वापस जमा करवा दी गई। इस तरह जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने मिलकर अर्डैस के माध्यम से ठेकेदारों को आजीविका भवन बनाने का ठेका दे दिया और अपर मुख्य सचिव पंचायत ग्रामीण विकास विभाग राष्ट्रीय मुद्रा जुलानिया के आदेश को ताक में रखते हुए उसकी धज्जियां उड़ा दी।

अपर मुख्य सचिव के आदेश में स्पष्ट रूप से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि, आजीविका भवन के निर्माण का काम ग्रामीण महिलाओं द्वारा गठित संकुल स्तरीय संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। परंतु आजीविका मिशन और जिला पंचायत के अधिकारियों की सांस्कृतिक चलते उन्होंने अपने स्वाधीन के लिए काम की प्रक्रिया को पूरी की गई और सकार की गशि को चुना लगाया गया। जोट विकासखंड का आजीविका भवन शहर से दूर ग्राम कदमों में ऐसी जगह बनाया गया है जो महिलाओं के लिए सुविधाजनक और काम के अंदर हो। परंतु अलीराजपुर जिले के अंदर कई स्थानों पर आजीविका भवन ऐसे स्थानों पर बना दिए गए, जिनकी उपयोगिता ही नहीं है और महिलाओं के लिए सुविधाजनक भी नहीं है। इस तरह जनता की टेक्स की गशि का दुरुपयोग कर केवल औपचारिक रूप से सहित कुल 40 लाख रुपए का आजीविका भवन अपनी दुरुस्त पर असुंग बहा रहा है। जिला प्रशासन और राज्य सकार के नुमाइंदे, मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नाम रोड से कई बार

आदेश के बिंदु क्रमांक 2.1 में भवन निर्माण के लिए 5000 वर्ग फीट जमीन विकासखंड स्तर पर अथवा कर्बे के अंदर उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए थे। साथ ही महिलाओं के लिए आजीविका भवन ऐसे स्थान पर बनाने के लिए लिखा गया था जहां वह जगह महिलाओं के लिए सुविधाजनक और काम के अंदर हो।

गारंटी नहीं है।

कार्य की प्रगति के आधार पर जिसमें लिख इसके सामने से निकल चुके हैं, क्या उनकी इस पर नजर नहीं पड़ी...?

## कुछ ऐसे प्रश्न जिन पर जांच की जाना चाहिए

- जप्रदेश के अपर मुख्य सचिव महिलाओं की स्थानों पर भरोसा करते हैं और उन्हें भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी देते हैं तो फिर उनको काम करने का अवधारणा नहीं दिया गया, ऐसा याचिया क्या गई...?

- किसके आदेश और निर्देश पर संकुल संगठनों के खाते से जिला पंचायत के खाते में राशि की वापसी करवाई गई...?

- ठेकेदारों के माध्यम से काम करने के लिए क्या प्रक्रिया की गई...?

- राज्य सकार के निर्माण का काम कितने समय होना चाहिए था। क्या हुआ

समय से पूरा हुआ...?

- कार्य का पूर्णांक प्राप्त किसने जारी किया और किस आधार पर जारी किया किया...?

- यद्यपि ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया गया यदि हां तो बाउडी वॉल और दूसरे काम समय पर याचिया करवाए गये...?

- ठेकेदारों को भुगतान कर्त्ता युरु करने से लेकर पूरा होने तक कितने किरती में और काम करवा किया है...?

एक दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड्डाल करेंगे ड्राइवर, मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन

माही की गूँज, अलीराजपुर।

ऑल ईंडिया ड्राइवर कल्याण संघ अपनी 29 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। संघ ने 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड्डाल का आहान किया है। अलीराजपुर जिले के ड्राइवर एसोसिएशन के जिलाल्याक्ष विजय डुडवे, उपाध्यक्ष कैलाश घिंडे ने बताया, मध्यप्रदेश भारत संघ के तत्वाधान में मानव में संघ के बैनर के तहत एक आदेश देकर जिला पंचायत के खाते में यह रकम वापस जमा करवा दी गई। इस तरह जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने मिलकर अर्डैस के माध्यम से ठेकेदारों को आजीविका भवन बनाने का ठेका दे दिया और अपर मुख्य सचिव पंचायत ग्रामीण विकास विभाग राष्ट्रीय मुद्रा जुलानिया के आदेश को ताक में रखते हुए उसकी धज्जियां उड़ा दी।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

विगत दिनों से धार्मिक स्थलों पर अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। दीपावली के बाद यह आयोजन होते हैं। अन्नकूट का तापयन ही स्नानत धर्म में वर्षा काल के चार माह में जिन खातों सामाजिकों का भोजन में विधि किया गया है। सभी सामाजिकों को दीपोत्सव बाद सभी को अन्नकूट कर प्रतिविनियत कर एक साथ बनाया जाता है। जिन खातों को एक देवताओं को समर्पित कर यानी कि भोग लगाने के बाद प्रसादी की रूप में ग्रहण कर प्रतिविनियत होता है। अम्बे माता की रूप से आयोजन की रूपी विधि विभाग राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जैन जीवन परिवार, दिनेश परिवार, लुधियाना सुरेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष लुधियाना पंजाब धारा जिले से महेश चन्द्रन्सी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दिनेश रुधवंशी शामिल हुए।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

विगत दिनों से धार्मिक स्थलों पर अन्नकूट का तापयन ही स्नानत धर्म में वर्षा काल के चार माह में जिन खातों सामाजिकों का भोजन में विधि किया गया है। अलीराजपुर जिले के एक बड़ी आबादी बड़े जंगलों और दूसरे गांवों में निवास करती है। आजादी के देवताओं को समर्पित कर एक साथ बनाया जाता है। जिन खातों को एक देवताओं को समर्पित कर यानी कि भोग लगाने के बाद प्रसादी की रूप से आयोजन की रूपी विधि विभाग राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जैन जीवन परिवार, दिनेश परिवार, लुधियाना सुरेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष लुधियाना पंजाब धारा जिले से महेश चन्द्रन्सी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दिनेश रुधवंशी शामिल हुए।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

आंवला नवमी पर अम्बे माता को छप्पन भोग के साथ अन्नकूट संपत्ति

माही की गूँज, आम्बुआ।

आंवला नवम

